CLC INDUSTRIES LIMITED

(Formally known as Spentex Industries Limited)

23rd January, 2025

To,

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400051
Maharashtra, India.
Symbol: SPENTEX

BSE Limited
Listing Compliance Department
Floor 25, P J Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001
Maharashtra, India.

Scrip Code: 521082

Dear Sir / Madam

Sub.: NEWSPAPER CUTTING U/R 30 OF THE SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

REF: PUBLICATION OF FINANCIAL RESULTS U/R 33 OF THE SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

With respect to above subject, this is to inform the stock exchanges that pursuant to Regulation 30, 33 and 47 read with Part A (12) of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and in continuation to our letter dated 22nd January 2025 with regard to outcome of Board meeting held on 22nd January 2025, the extracts of Un-audited Financial Results for the quarter & nine months ended 31st December, 2024 was published for the information of Shareholders in Danik Savera – New Delhi & The Morning Standard -New Delhi.

Copy of newspapers clippings in this connection are attached.

You are requested to kindly take the above information on record.

Thanking you.

Yours Faithfully,

For CLC Industries Limited

KOYAL GEHANI

Digitally signed by KOYAL GEHANI
DN: c=IN, o=Personal, 2.5.4.20=88252aa0b4b6d502defe9916551a8cc0ba4ba866951d5f34d5a429f15c195ea2, postalCode=431001, st=Maharashtra, serialNumber=31a74fa71a2eb092486adbc8980137bafe05bb840a48a0f1f1008636f80d1142, cn=KOYAL GEHANI
Date: 2025.01.23 13:43:21 +05'30'

Koyal Gehani
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No-A-45277
Encl: As above

Registered Office: A-60, Okhla INDL Area Phase II, New Delhi, India, 110020
Correspondence Address: 318, N-3, CIDCO, Jalna Road, Aurangabad-431003, Te1.0240-6608663
Phone: +91-240 6608636/2473363| **Fax:** +91-240 2473563 |
Email Id: companysecreatary@clcindustries.com
Website: www.clcindiacom |**CIN:** L74899DL1991PLC138153

महाकुम्भ से योगी ने दी महासौगात, यूपी बनेगा एयरोस्पेस का महारथी

महाकुम्भ नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक, 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

सवेरा न्यूज

महाकुम्भ नगर, 22 जनवरी : विश्व के सबसे बड़े धार्मिक-सामाजिक समागम 'महाकुम्भ 2025' में जहां एक तरफ दुनियाभर के आस्थावानों का जुटान हो रहा है, वहीं प्रदेश की योगी सरकार ने भी इस महाकुम्भ के जरिए सूबे को महा सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को तीर्थराज प्रयागराज में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें योगी सरकार ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें उत्तर प्रदेश को एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में 'महारथी' बनाने के उद्देश्य से नई नीति को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 50 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है। इस नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के 1 लाख युवाओं को सीधे-सीधे रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है। महाकुम्भ नगर से प्रदेश को महासौगात देने के क्रम में अन्य अहम प्रस्तावों में विदेशी कंपनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए एफडीआई नीति में योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके अंतर्गत योगी सरकार भूमि पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। इसके अलावा यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति में भी बड़े सुधारों की तरफ योगी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं।

एआई और सॉफ्टवेयर डिवैल्पमैंट सैंटर को भी किया जाएगा प्रोत्साहित : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट मंशा है कि राज्य में उन कंपनियों के विकास को बढ़ावा दिया जाए जो ए एंड डी में भारत की आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण का समर्थन करती हो। इस नीति के जरिए ए एंड डी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर विकास केंद्र को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति के अंतर्गत अगले पांच साल में 50 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित करने के साथ ही 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। इस नीति के अंतर्गत ए एंड डी सेक्टर की यूनिट्स को फ्रंट एंड सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इसमें लैंड सबसिडी, स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन और कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी। साथ ही परिवहन शुल्क पर छूट जैसी सुविधाएं भी योगी सरकार प्रदान करेगी। यही नहीं महिला उद्यमियों को इस नीति के जरिए बड़ी राहत दी जाएगी।

यूपी में एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाना है उद्देश्य

महाकुम्भ नगर के त्रिवेणी संकुल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी एयरोस्पेस तथा रक्षा केंद्र बनाने पर है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी क्षमताओं, नवाचार और वैश्विक सहयोगी को गति मिल सकेगी। इस नीति का उद्देश्य यूपी में एयरोस्पेस और रक्षा (ए एंड डी) क्षेत्र को सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा (यूपीडीआईसी) में एक मजबूत, विश्व स्तरीय, उच्च प्रौद्योगिकी और कुशल ए एंड डी मैन्यूफैक्चरिंग वातावरण बनाना है। इसके अलावा ए एंड डी क्षेत्र में आधुनिकतम केंद्र विकसित करने के लिए स्टार्टअप और निवेश को भी आकर्षित किया जाएगा। यही नहीं यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा में स्टार्टअप और एमएसएमई के कौशन और क्षमता विकास के लिए ए एंड डी आधारित सामान्य सुविधा केंद्र बनाने पर भी योगी सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है। राज्य में प्रमुख ए एंड डी विनिर्माण परियोजनाओं और डीपीएसयू को आकर्षित करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना भी इस नीति का प्रमुख हिस्सा है।

महाकुम्भ में त्रिवेणी तट पर बड़ा फैसला, काशी तक आएगी गंगा एक्सप्रैस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रैस-वे से भी होगी कनैक्ट

सवेरा न्यूज

महाकुम्भनगर, 22 जनवरी : तीर्थराज प्रयाग में 144 वर्ष के बाद महाकुम्भ के शुभ संयोग पर लोककल्याण का संकल्प लेकर बैठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में बेहतर कनैक्टिविटी के लिए बड़े फैसले लिए हैं। पावन त्रिवेणी तट पर हुई कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक में 320 किलोमीटर लंबाई वाले विंध्य एक्सप्रैसवे और 100 किमी लंबाई वाले विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को सैद्धांतिक सहमति दी गई। विशेष कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित और प्रकरण एक्सप्रैसवे के माध्यम से कनैक्टिविटी नैटवर्क विकास और क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं का विकास हो रहा है। वर्तमान में प्रदेश के पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र एक्सप्रैसवे से आच्छादित हैं और अब दूरवर्ती दक्षिणी-पूर्वी विंध्य क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से प्रयागराज मीरजापुर, वाराणसी, चंदौली एवं सोनभद्र को जोड़ते हुए 320 किलोमीटर लंबाई वाले नए नए एक्सप्रैसवे का निर्माण किया जाना चाहिए। इस नए एक्सप्रेस में का प्रारंभ बिंदु प्रयागराज में गंगा एक्सप्रैसवे होगा, जबकि सोनभद्र में एनएच 39 पर इसका समापन होगा। इस तरह गंगा एक्सप्रैसवे और विंध्य एक्सप्रैसवे की सीधी कनैक्टिविटी होगी, साथ ही, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में झारखंड से भी अच्छा संपर्क स्थापित हो सकेगा। इसी प्रकार, विंध्य एक्सप्रैसवे पर चंदौली से प्रारंभ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतिम बिंदु गाजीपुर तक विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाना उचित होगा। इसकी लंबाई लगभग 100 किमी होगी। प्रयागराज को बड़ा उपहार देते मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में सलोरी से हेतापट्टी तक नए ब्रिज के निर्माण की भी आवश्यकता जताई।

एससीआर की तर्ज पर प्रयागराज-चित्रकूट और वाराणसी के लिए बनेंगे दो नए डिवैल्पमैंट रीजन

सवेरा न्यूज

महाकुम्भ नगर, 22 जनवरी : प्रदेश के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने महाकुम्भ में त्रिवेणी तट पर कैबिनेट बैठक करके विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद की इस ऐतिहासिक बैठक में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों तक विकास को प्रशस्त करने के लिए स्वीकृत किए गए 'मास्टर प्लान' के अंतर्गत जहां स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर दो नए रीजन बनाए जाएंगे, वहीं दो नए लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा और यमुना नदी पर दो बड़े पुलों का भी निर्माण किया जाएगा। इन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी बुधवार को महाकुम्भ नगर में आयोजित कैबिनेट की बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को दी। इस अवसर पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित मंत्रीपरिषद् के सभी सदस्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 144 वर्ष के अंतराल पर प्रयागराज में महाकुम्भ के शुभ संयोग पर महाकुम्भ नगर में मंत्रीपरिषद् की अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में चित्रकूट, प्रयागराज, मीरजापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

प्रयागराज-चित्रकूट डिवैल्पमैंट रीजन को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज-चित्रकूट डिवैल्पमैंट रीजन को स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) की तर्ज पर विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। यह क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा और इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

वाराणसी-विंध्य डिवैल्पमैंट रीजन पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में वाराणसी-विंध्य डिवैल्पमैंट रीजन के विकास को प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए विशेष योजनाओं पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ए सभी परियोजनाएं प्रदेश की बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेंगी और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी।

गंगा एक्सप्रैसवे का विस्तार

गंगा एक्सप्रैसवे को प्रयागराज से मिजार्पुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर तक विस्तार दिया जाएगा। यह नया लिंक एक्सप्रैसवे पूर्वांचल एक्सप्रैसवे से भी जुड़ जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनैक्टिविटी और सशक्त होगी। इसके अलावा वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रैसवे बनाया जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट को 'प्रयागराज-विंध्य-काशी एक्सप्रैसवे' के रूप में विकसित किया जाएगा।

नए पुलों और ब्रिजों का निर्माण : सीएम योगी ने कहा कि यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नए सिक्स लेन पुल के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सलोरी-हेतापट्टी-झूंसी के बीच फोर लेन ब्रिज की मंजूरी दी गई है, जो प्रयागराज को मीरजापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर से जोड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। साथ ही रीवा नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी गई है।

पेज 1 के शेष

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कच्चे...

औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है।

गौरलतब है कि 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जूट उद्योग पर निर्भर है। जूट मिलों और जूट के व्यापार से करीब 4 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। गत वर्ष 1.7 लाख किसानों से जूट की खरीद की गई थी। जूट उत्पादन में 82 प्रतिशत किसान पश्चिम बंगाल से हैं, जबकि असम तथा बिहार की जूट उत्पादन में 9-9 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। विज्ञप्ति में कहा गया, भारतीय जूट निगम (जेसीआई) मूल्य समर्थन परिचालन के लिए केन्द्र सरकार की नोडल एजैंसी के रूप में काम करना जारी रखेगी। ऐसे परिचालनों में होने वाले नुक्सान (यदि कोई हो) की पूरी भरपाई केन्द्र सरकार करेगी।

लोग अब खुलकर आप...

'दिल्ली वाले आप वालों की आप-दा और उनके झूठ एवं फरेब से अब ऊब चुके हैं।

पहले कांग्रेस ने और फिर आप वालों की आप-दा ने दिल्ली के लोगों से बहुत विश्वासघात किया है।' उन्होंने कार्यकर्त्ताओं से 'आप-दा' वालों की पोल खोलने और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों के लिए 'आप-दा' बताते आ रहे हैं।

उन्होंने 'आप' पर पूर्वांचल के लोगों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर निकालने की साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी में उनके लिए नफरत भरी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में...

(हिन्दू वादियों द्वारा दायर मुकद्दमों के समेकन के खिलाफ), दूसरा है खुद अधिनियम (पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को चुनौती)। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करें।' पीठ ने कहा कि इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक जारी रहेगी जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब...

बातचीत के लिए आगे आए हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, दोनों पक्ष बातचीत करने और 14 फरवरी, 2025 को चंडीगढ़ में मामले का निपटारा करने पर सहमत हुए हैं। डल्लेवाल चिकित्सा सहायता लेने के लिए राजी हो गए हैं। उनकी हालत में सुधार हुआ तथा उन्हें किसानों के प्रदर्शन स्थल से 50 मीटर दूर एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

पंजाब के अधिवक्ता ने कहा कि 100 से अधिक किसानों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। डल्लेवाल ने अपना अनशन समाप्त किए बिना ही डॉक्टर के परामर्श के अनुसार चिकित्सा सहायता ली है। पीठ ने आगे कहा, हम डल्लेवाल को यह समझाना चाहेंगे कि वह बैठक से कुछ दिन पहले चंडीगढ़ जा सकते हैं। वह चंडीगढ़ के पीजीआई में उचित चिकित्सा जांच करा सकते हैं तथा प्रभावी भागीदारी के लिए आवश्यक चिकित्सा सहायता ले सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने भी डल्लेवाल से मुलाकात की थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में फरवरी के आखिरी सप्ताह अंत में सुनवाई करेगी।

संभल में शाही जामा मस्जिद...

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शिरीष चंद्र ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा कुएं को अवैध रूप से ढकने की शिकायत के बाद खुदाई शुरू की गई थी। हम इसे बहाल करने के लिए खुदाई कर रहे हैं और आगे की जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या कुआं ऐतिहासिक महत्व का है, एएसपी ने कहा, 'स्थानीय लोगों और बुजुर्ग निवासियों के अनुसार, यह कुआं सदियों से मौजूद है। खुदाई आगे बढ़ने पर इसकी पुष्टि हो सकेगी।

मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी...

योगी सरकार में यह दूसरा अवसर है, जब पूरे मंत्रिमंडल ने एक साथ कुम्भ के सुअवसर पर संगम स्नान किया है। इससे पूर्व 2019 में भी तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित कुम्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। तब मुख्यमंत्री और समस्त मंत्रिमंडल के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि और अन्य साधु संतों ने भी संगम की धारा में पवित्र स्नान किया था।

जद (यू) में कलह...

है। वहां एनडीए की जो सरकार है, उसे पूर्व की तरह (पार्टी का) समर्थन जारी रहेगा। वहां ही नहीं, बिहार और देश में एनडीए की मजबूती के लिए पहले की तरह हम उसी तत्परता के साथ अपना समर्थन जारी रखेंगे।

पीएसी की बैठक में...

बीच किराया को विनियमित करने के लिए एईआरए अधिनियम में संशोधन का आह्वान किया ताकि इस कानून को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा प्रणाली जवाबदेही तय करने में विफल रही है। सांसदों का कहना था कि अधिनियम को प्रभावी बनाने से निजी परिचालकों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। नागरिक उड्डयन सचिव और एईआरए प्रमुख उन लोगों में शामिल थे जो बैठक में समिति के सामने उपस्थित हुए। सूत्रों ने कहा कि पीएसी सदस्य, सामान्य तौर पर अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट थे और समिति ने उनसे विस्तृत जवाब देने को कहा है।

माऊंट एवरैस्ट पर चढ़ाई...

फीस नहीं देनी होगी।' इस बीच, नेपाल और चीन के बीच स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की योजना बनाने वालों को पतझड़ के मौसम में 5,500 डॉलर की जगह 7,500 डॉलर का भुगतान करना होगा। सर्दियों और मानसून के मौसम के लिए शुल्क 2,750 डॉलर से बढ़कर 3,750 डॉलर हो गया है। नेपाली पर्वतारोहियों के लिए, शुल्क 75,000 नेपाली रुपए (लगभग 545 डॉलर) से दोगुना होकर 150,000 रुपए (लगभग 1,090 डॉलर) हो गया है। नेपाल ने आखिरी बार 1 जनवरी 2015 को पर्वतारोहण परमिट शुल्क में संशोधन किया था।

पुष्पक एक्सप्रैस में आग...

माहेजी और परधाडे स्टेशनों के बीच हुई जहां शाम करीब 5 बजे लखनऊ-पुष्पक एक्सप्रैस में आग लगने की अफवाह के कारण किसी ने चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई।

मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता स्वप्निल नीला ने बताया कि पुष्पक एक्सप्रैस के कुछ यात्री नीचे उतर गए और बेंगलुरु से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रैस की चपेट में आ गए। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमारी प्रारंभिक जानकारी है कि पुष्पक एक्सप्रैस के एक कोच में 'हॉट एक्सिल' या 'ब्रेक बाइंडिंग' (जैमिंग) की वजह से चिंगारी निकली और कुछ यात्री घबरा गए। उन्होंने चेन खींच दी और उनमें से कुछ नीचे कूद गए। उसी समय पास की पटरी से कर्नाटक एक्सप्रैस गुजर रही थी।' मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि जलगांव जनरल अस्पताल और आसपास के अस्पतालों को हादसे में घायल यात्रियों के उपचार के लिए तैयार रखा गया है। दावोस गए फड़नवीस ने 'एक्स' पर लिखा, 'राज्य के मंत्री गिरीश महाजन और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए हैं।

आरजी कर मामला : सुप्रीम...

अदालत ने सोमवार को मृत्यु होने तक जेल की सजा सुनाई थी। पिछले साल 9 अगस्त को चिकित्सक के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की जानी थी। इस जघन्य अपराध से देश में आक्रोश फैल गया था तथा पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक प्रदर्शन हुए थे।

रहस्यमयी मौतों के बाद राजौरी का गांव निषिद्ध क्षेत्र घोषित

सवेरा न्यूज

राजौरी/जम्मू, 22 जनवरी : जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के बधाल गांव में 3 परिवारों के 17 लोगों की मौत और एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने के बाद गांव को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि उसी गांव के एक और व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत सभी सार्वजनिक और निजी आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। बीएनएसएस की धारा 163 जिलाधिकारी को अत्यावश्यक परिस्थितियों में लिखित आदेश जारी करने की शक्ति देती है। इन आदेशों का उपयोग उपद्रव या खतरों को रोकने या उनका समाधान करने के लिए किया जा सकता है। अतिरिक्त जिलाधिकारी (राजौरी) राजीव कुमार खजूरिया द्वारा जारी आदेश में गांव को 3 निषिद्ध क्षेत्रों में बांटा गया है। पहले जोन में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनमें मौत हुई हैं। इन घरों को सील कर दिया जाएगा और वहां किसी के भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

दूसरे जोन में उन परिवारों को रखा गया है जो प्रभावित लोगों के करीबी संपर्क में आए थे। इन लोगों को राजौरी के सरकारी मैडीकल कालेज में भेजा गया है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। आदेश के अनुसार, तीसरे जोन के तहत पूरे गांव को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच 3 संबंधित परिवारों के 17 सदस्यों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। मंगलवार शाम को 24 वर्षीय अयाज अहमद की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

प्रभावित परिवार प्रशासन द्वारा उपलब्ध भोजन और पानी का ही उपयोग करेंगे : प्रशासन ने आदेश दिया है कि प्रभावित परिवार और उनके करीबी संपर्क वाले लोग केवल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए भोजन और पानी का ही उपयोग करेंगे। घरों में उपलब्ध अन्य खाद्य पदार्थों का उपभोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी खाद्य और जल आपूर्ति को तुरंत बदला जाएगा और प्रभावित घरों से खाद्य सामग्री जब्त की जाएगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मंगलवार को गांव का दौरा किए जाने के बाद सख्त आदेश दिए गए हैं।

खालिदा जिया विध्वंसक गतिविधि से संबंधित 10 साल पुराने मामले में बरी

सवेरा न्यूज/एजैंसी (ढाका): बंगलादेश की एक अदालत ने बीएनपी की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को विध्वंसक गतिविधि से संबंधित 10 साल एक पुराने मामले में बरी कर दिया। कॉमिला जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अदालत द्वितीय) अफरोजा जस्मीन ने यह आदेश पारित किया क्योंकि जिया (79) के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जिया फिलहाल लंदन में इलाज करवा रही हैं।

Central team inspects moisture in paddy

TN farmers want moisture norm to be hiked from 17% to 22% to qualify for govt procurement and MSP

EXPRESS NEWS SERVICE @ Thanjavur/Tiruchy

A four-member team of officials deputed by the union government's food and public distribution department to assess the moisture content of paddy affected by the unseasonal rainfall in delta districts began its four-day tour by visiting the farmlands in Thanjavur on Wednesday. The team also collected samples of paddy brought by farmers to Direct Procurement Centres (DPC) for testing their moisture content in a laboratory.

According to sources, over 3.40 lakh hectares of paddy crop across the region is yet to be harvested and the crops face the risk of being rejected at the procurement centres if the moisture norms are not relaxed by the union government, sources said. Farmers want the moisture norm for paddy to be hiked from 17% to 22% to qualify for government procurement and minimum support price.

In Thanjavur and Tiruvarur districts, of the 2.73 lakh hectares of samba and thalady paddy crops, 2.25 lakh hectares are yet to be harvested. Similarly, 1.18 lakhs hectares of paddy out of 1.31 lakh hectares in Mayiladuthurai and Nagapattinam is yet to be harvested. Livelihood of lakhs of farmers in the region is at stake, sources said.

The team comprising assistant directors (storage and research) Preeti Shukla and V Naveen and technical officers Rahul and Abhisek Pandey first visited the DPC at Kakkarai near Orathanadu and listened to the grievances of farmers before collecting the samples. R Sukumaran, a farmer, told the team that since the ground is wet, farmlands are inundated, and there is misty condition in the region, they could not dry the paddy.

A Annadurai, Managing Director of TNCSC which is procuring the paddy on behalf of Food Corporation of India, who accompanied the team, said the request to relax the moisture norm was necessitated due to the rains in January.

3.4L hectares of paddy not harvested

According to sources, over 3.40 lakh hectares of paddy crop across the region is yet to be harvested and the crops face the risk of being rejected at the procurement centres if the moisture norms are not relaxed by the union govt

Commission to probe Tirupati stampede

Finish probe in 6 months

Commission should finish its probe within six months from the date of assumption of charge, and submit report to the govt.

EXPRESS NEWS SERVICE @ Vijayawada

THE State government has constituted the Commission of Inquiry headed by M Satyanarayana Murthy, former Andhra Pradesh HC Judge, to probe the stampede at Padmavathi Park in Tirupati on January 8 during the distribution of Sarva Darshan tokens for Vaikunta Dwara Darshan, in which six pilgrims were killed.

The Commission of Inquiry set up under the Commissions of Inquiries Act, 1952 should complete its probe within six months from the date of assumption of charge, and submit its report to the government. Chief Secretary K Vijayanand issued an order on Wednesday, constituting the Commission of Inquiry.

ISRO dispatches crew module for Gaganyaan

EXPRESS NEWS SERVICE @ Hyderabad

THE Indian Space Research Organisation's (ISRO) Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC) dispatched the crew module for the first uncrewed Gaganyaan (G1) mission after successfully integrating it with the liquid propulsion system on January 21, 2024. The crew module was dispatched to Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC).

The liquid propulsion system, called the Crew Module Propulsion System, is a bi-propellant-based Reaction Control System and is meant for pitch, yaw and roll (a precise three-axis control) of the crew module.

The control will be initiated following separation of service module during the descent and atmospheric re-entry phase until the deployment of parachute-based deceleration system. The system employs twelve 100N thrusters, pressurisation system with high pressure gas bottles and the propellant feed system along with the associated fluid control components, ISRO said.

The Crew Module Uprighting System (CMUS), designed by VSSC, was also integrated with the crew module at LPSC. The crew module will undergo further integration operations at the VSSC, including avionics package assembly, electrical harnessing and checks before it is sent to the UR Rao Satellite Centre in Bengaluru for the final phase of integration of the orbital module. Gaganyaan-G1 — expected to be launched in early part of this year — and the subsequent two uncrewed missions Gaganyaan-G2 and G3 will lead to India's maiden human spaceflight.

Orissa HC quashes FIR, asks students to visit jail, submit report on hygiene

EXPRESS NEWS SERVICE @ Cuttack

THE Orissa High Court has quashed an FIR against five students on the condition that they will visit a jail, observe living conditions of the prisoners and submit a report. The FIR was registered against the five, all students of a college in Cuttack city, for assaulting and threatening to kill a classmate. In the order, Justice Sibo Sankar Mishra said subjecting the petitioners who are young students pursuing their graduation 'to the rigors of the trial would be a futile exercise and quashed the FIR subject to conditions.'

"The petitioners shall visit Choudwar Jail, Cuttack within two weeks from today, compile a report regarding the hygiene maintained on the jail premises and suggest positive measures regarding the same. They must furnish their suggestions to the jail superintendent and obtain a certificate from him to be filed before this court within four weeks from today," Justice Mishra said in his January 16 order, while quashing the FIR.

The FIR was registered at Madhupatna police station on the basis of a complaint lodged by the victim's father on December 30, 2024. The petitioners were directed by the HC to tender unconditional and unqualified written apologies to the informant, father of the victim and file those written apologies before the court within ten days.